बारिश से टूटी सड़कों को सुधारने के लिए 1445 करोड़ रुपए का बजट आवंटित

इनमें से 645 करोड़ रु. पेचवर्क रिपेयरिंग तथा 800 करोड़ रु. स्थायी मरम्मत पर खर्च होंगे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा एन.एच.ए.आई. की परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य करें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने बारिश से टूटी सड़कों को सुधारने के लिए 1445 करोड़ रु. का बजट आवंटित किया है।

इनमें से 645 करोड़ रु. पेचवर्क रिपेयरिंग तथा 800 करोड़ रु. स्थायी मरम्मत पर खर्च होंगे। मुख्य सचिव ने पेच रिपेयर कार्य 15 नवम्बर तक उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दूसरे विभागों के इंजीनियर्स से इन कामों की जांच करवाई जाएगी।

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भावना के अनुरूप सभी अधिकारी ईमानदारी से काम करते हुए फील्ड में सक्रिय रहकर स्वीकृत कार्यों को समय पर पूर्ण करवाएं। सिर्फ अपवाद की स्थिति में ही निविदा की तिथि को आगे बढ़ाएं।

अन्यथा निविदा खोलने से वर्क ऑर्डर जारी करने तक निर्धारित टाइमलाइन का सख्ती से पालना किया जाए तथा उसका निरीक्षण ऑनलाईन माध्यम से करें।

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा एन.एच.ए.आई. की परियोजनाओं की समीक्षा की।

स्पेशल टास्क फोर्स गठन के निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव ने एनएचएआई-एनएच के कार्यों में अन्तर्विभागीय मुद्दों के त्वरित निस्तारण के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए। टास्क फोर्स में वन, राजस्व, विद्युत व अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा।

उन्होंने एनएचएआई की 7919 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश में चल रही इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए पूर्ण सहयोग एवं सामंजस्य से काम करें।

लम्बित कामों को मार्च तक पूरा करें

मुख्य सचिव ने पीडब्ल्यूडी के 50 करोड़ रुपये की लागत से अधिक के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जो 35 लम्बित कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें 31 दिसम्बर तक एवं शेष 8 कार्यों को मार्च, 2026 तक पूर्ण करें।

गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी के 50 करोड़ रुपये की लागत से अधिक के 33 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 31 निर्धारित समयावधि में चल रहें हैं एवं 43 कार्यों की निर्धारित समयावधि निकल चुकी है।

पी.एम.आई.एस. की सराहना की

मुख्य सचिव ने विभाग द्वारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए काम लिए जा रहें प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफर्मेशन सिस्टम की सराहना करते हुए कहा कि इसे और सुदृढ़ किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि इसमें हर प्रोजेक्ट की प्रत्येक स्थिति की 3-4 उच्च गुणवत्ता की फोटो डाली जाए। इसके साथ ही, उन्होंने डीएलपी सड़कों के निरीक्षण के लिए विभाग द्वारा विकसित किए गए सुगम पथ एप की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

- **मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अफसरों को प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कें प्राथमिकता और गुणवत्ता के साथ सुधारने के निर्देश दिए**

हर माह होगी बड़े प्रोजेक्टस की समीक्षा

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए है कि सरकार की मंशा के अनुरूप बजट घोषणाओं एवं मुख्यमंत्री घोषणाओं को समय पर पूर्ण कर आमजन को उनका शीघ्र लाभ सुनिश्चित करने के लिए विभाग के प्रोजेक्टस की हर माह समीक्षा की जाएगी।

गत 2 वर्षो में 36140 कि.मी.लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ

अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने बैठक में बताया कि बजट घोषणा 2024-25 व 2025-26 के तहत लगभग 15 हजार करोड़ रुपये की लागत के 12 हजार से अधिक कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से अधिकांश कार्य आरंभ करवाये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि विगत 2 वर्षो में 24,976 करोड़ रुपये व्यय कर 36140 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का विकास प्रदेश में करवाया जा चुका है। इस दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिलों में होगी पदयात्राएं

जयपुर में 31 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे गांधी सर्किल से शुरू होगी पदयात्रा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । केन्द्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने गत 6 अक्टूबर को सरदार150 कम्यूनिटी मार्च अभियान शुरू किया है। 2 माह तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अभियान का समापन आगामी 6 दिसम्बर को होगा। इस अभियान को पूर्ण जन भागीदारी से संचालित कर देशवासियों विशेषकर युवाओं को सरदार पटेल की विरासत के बारे में जागरूक कर विरासत के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक कृतज्ञता अर्पित करने, उनमें राष्ट्रीय एकता और देश सेवा की भावना को अधिक विकसित करना है।

31 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक जिला स्तरीय पदयात्राएं आयोजित होंगी। 26 नवम्बर को सरदार पटेल की जन्म स्थली करमसाड़ से 150 किमी लम्बी पदयात्रा शुरू होगी। इस पदयात्रा के 6 दिसम्बर को एकता नगर (स्टेच्यू ऑफ यूनिटी) पहुंचने के साथ ही अभियान का समापन होगा। आगामी 31 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे जयपुर के गांधी सर्किल से एकता मार्च का भव्य शुभारंभ किया जाएगा। एकता मार्च का मार्ग जयपुर के गांधी सर्किल से बिड़ला मंदिर रामबाग, अंबेडकर सर्किल होते हुए अमर जवान ज्योति तक रहेगा।

- **इसके बाद 26 नवम्बर को सरदार पटेल की जन्म स्थली करमसाड़ से 150 किमी लम्बी पदयात्रा शुरू होगी, जो 6 दिसम्बर को एकता नगर (स्टेच्यू ऑफ यूनिटी) पहुंचने के साथ संपन्न होगी**

इस अभियान में युवा मामले, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, सूचना एवं जनसम्पर्क और गृह विभाग, माई भारत और एनएसएस के कार्मिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

यह अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण कड़ी है। नागरिकों को पदयात्रा, प्रतियोगिता आदि पहल के माध्यम से इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। यूनिटी मार्च सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के सम्मान में एक राष्ट्रव्यापी पहल है। यह श्एक भारतकृ श्रेष्ठ भारत के घटक के रूप में देश को एकजुट करने में सरदार पटेल की अद्वितीय भूमिका का प्रतीक है, यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के मिशन की कड़ी है। इस अभियान में युवाओं की बेहतर भागीदारी के लिए सरदार150 यंग लीडर्स क्विज, सरदार150 रील कम्पीटिशन और सरदार150 निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।

पदयात्रा के साथ-साथ जिलों में विकासात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जल निकायों में स्वच्छता अभियान, सरदार उपवन पहल के तहत पौधारोपण, महिला कल्याण शिविर, योग और स्वास्थ्य शिविर और वोकल फॉर लोकल अभियान शामिल हैं।

इन गतिविधियों का उद्देश्य नागरिकों को जुटाना, स्थानीय नवाचार का जश्न मनाना और युवा ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाना है।

'खतरनाक यात्री बसों के संचालन पर प्रभावी कार्रवाई करें'

जयपुर । राज्य मानवाधिकार आयोग ने मनोहरपुर में यूपी के पीलीभीत से आ रही बस के हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से आग लगने और उसमें बैठे कई यात्रियों के मरने के हादसे में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। वहीं परिवहन आयुक्त से कहा है कि उनसे अपेक्षा है कि वे प्रदेश में चल रही यात्री बसों की सुरक्षा के मापदंडों को सुनिश्चित करें। इसके अलावा खतरनाक यात्री बसों के संचालन पर प्रभावी कार्रवाई करें। वे यह भी देखें की बसों में यात्रियों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम हों और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों की पालना की जाए। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश मनोहरपुर बस हादसे पर प्रसंज्ञान लेते हुए दिए।

राज्यपाल बागड़े से उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की भेंट

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने राज्यपाल को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। शिष्टाचार भेंट के दौरान दोनों के बीच राज्य के जनकल्याणकारी विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। राज्यपाल ने उपमुख्यमंत्री को अपने प्रेरणादायी मार्गदर्शन से अवगत कराया तथा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य करने का आव्हान किया।

भजनलाल सरकार ने करीब 5 लाख किसानों से अब तक खरीदी 8191 करोड़ रुपये की उपज

राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से कृषक लाभांवित

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद योजना का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन कर किसानों से बड़े स्तर पर कृषि जिंसों की खरीद की जा रही है। समर्थन मूल्य पर वृहद् स्तर पर हो रही खरीद से किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से मुक्ति मिल रही है और उनकी सुनिश्चित आय हो रही है।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार के 2 वर्ष से भी कम अवधि के अब तक के कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में विभिन्न जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आनुपातिक दृष्टि से अधिक खरीद कर किसानों को प्रत्यक्ष रुप से लाभान्वित किया गया है।

- **प्रदेश में मूंग, मूंगफली और सोयाबीन की हुई रिकॉर्ड खरीद**

उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक लगभग 5 लाख किसानों से 8 हजार 191 करोड़ रुपये की उपज खरीदी जा चुकी है। वहीं, खरीफ-2025 सीजन में भी एमएसपी पर कृषि जिंस बेचान के लिए बड़ी संख्या में किसान अपना पंजीयन करवा रहे है। दक ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 5 वर्ष में 2827 करोड़ रुपये राशि का 3.90 लाख मीट्रिक टन मूंग किसानों से खरीदा गया था, जिसकी तुलना में वर्तमान सरकार के 2 वर्ष से भी कम अवधि के कार्यकाल में 1720 करोड़ रुपये का भुगतान कर किसानों से लगभग 2 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदा जा चुका है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मूंगफली रिकॉर्ड खरीद की गई है। पूर्ववर्ती सरकार के पूरे कार्यकाल में 1 लाख 74 हजार 656 किसानों से 2058 करोड़ रुपये राशि की 4.79 लाख मीट्रिक टन मूंगफली खरीदी गई थी। जबकि, वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में ही 1 लाख 42 हजार 58 किसानों से 3 हजार 269 करोड़ रुपये राशि की 4 लाख 84 हजार 687 मीट्रिक टन मूंगफली खरीदी जा चुकी है।

मादक पदार्थ तस्करों को 10 साल की सजा

जयपुर । एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत, महानगर प्रथम ने मादक पदार्थ कोकीन की तस्करी करने वाले अभियुक्त तैय्यब रहमान और रविन्द्र टकसाली को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर 2.45 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी प्रदीप कुमार मोदी ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा समय में मादक पदार्थ के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। मादक पदार्थ आसानी से उपलब्ध होने के चलते युवा वर्ग इसकी चपेट में आ रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरत सकते।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंकर लाल ने बताया कि विभाग की क्षेत्रीय इकाई जोधपुर के आसूचना अधिकारी को 10 मार्च 2023 को गोपनीय सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति तैय्यब रहमान लोक परिवहन की बस में बैठकर अपने बैग में कोकीन छिपाकर दिल्ली से जयपुर लाएगा। यह बस 13 मार्च 2023 को नारायण सिंह सर्किल पर शाम 6 से 6.30 बजे आएगी।

ड्रग की डिलीवरी जयपुर में रविन्द्र टकसाली को होनी है। सूचना पर एनसीबी टीम ने घटना वाले दिन शाम को संबंधित बस को रुकवाया और उसमें बैठी सवारियों की तलाशी ली। इसमें गोपनीय सूचना से मिलता-जुलता व्यक्ति तैय्यब रहमान मिला।

RIICO GROW WITH RAJASTHAN

RISING RAJASTHAN REPLETE • RESPONSIBLE • READY

प्रत्यक्ष आवंटन योजना - 2025

राइज़िंग राजस्थान में MoU करने वाले निवेशकों के लिए भूखण्ड के आरक्षित मूल्य पर

औद्योगिक भूखण्डों का डायरेक्ट अलॉटमेंट

छठा चरण

ऑनलाइन पोर्टल पर दिनांक 30.10.2025 (प्रात: 10:00 बजे) से 13.11.2025 (सायं 6 बजे) तक आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।

नियोजित लॉजिस्टिक भूखण्डों का आवंटन आरक्षित मूल्य पर | ई-लॉटरी | 18 नवंबर, 2025

100 औद्योगिक क्षेत्र | 5,971 कुल औद्योगिक भूखण्ड | 5,933 अनारक्षित भूखण्ड | 38 लॉजिस्टिक भूखण्ड

विभिन्न श्रेणियों / वर्गों के लिए आरक्षित भूखंड

221 अनुसूचित जाति/जनजाति | 220 महिला वर्ग | 115 भूतपूर्व सैनिक | 144 बेंचमार्क दिव्यांगता | 66 सशस्त्र बलों/अर्ध सैनिक बलों के मृतक के आश्रित

आवंटन की प्रक्रिया

एक भूखण्ड पर एक ही आवेदक होने पर सीधा आवंटन तथा एक से अधिक आवेदक होने पर ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन

EMD - भूखण्ड की कुल देय प्रीमियम राशि की 5 प्रतिशत राशि आवेदन के साथ ही ऑनलाइन जमा।

पात्रता - निवेशक जिन्होंने 14/10/2025 तक राइजिंग राजस्थान में राज्य सरकार के साथ एमओयू किये हैं वे सभी इस योजना में भूखण्ड के लिए पात्र हैं।

आवेदन हेतु स्कैन करें

भूखण्ड की राशि का भुगतान

*25% भुगतान के बाद, शेष 75% भुगतान 11 किश्तों में 8.5% ब्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भुगतान

या

RIICO की टर्म लोन स्कीम के तहत भूमि की लागत का 75% तक का ऋण 5 साल की पुनर्भुगतान अवधि एवं 8.5% ब्याज के साथ

औद्योगिक क्षेत्रों में नियोजित लॉजिस्टिक भूखण्डों के आवंटन से संबंधित पॉलिसी riico.rajasthan.gov.in पर देखें।

इस योजना के तहत भूखण्ड देखने या आवेदन करने के लिए https://riico.rajasthan.gov.in पर दिए गए Direct Land Allotment लिंक पर क्लिक करें अथवा SSO Portal पर login के बाद RIICO के आइकन पर क्लिक करके Land Allotment पर जाएं और Direct Land Allotment Policy - 2025 (for RR MoU Holders) पर क्लिक करें।

*केवल औद्योगिक भूखण्डों के लिए

राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005

हैल्पलाइन नंबर : 0141 4593250, 4593237 | वाट्सएप : +91 90013 06515 | ई-मेल : riico@riico.co.in

riico.rajasthan.gov.in · riicogis.rajasthan.gov.in/riicogiscitizen

राज.संवाद / सी / 25 / 12805

मतदाता सूची का पुनरीक्षण देशहित में कदम : मदन राठौड

जयपुर, (कासं)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को सकारात्मक और देश हितकारी पहल बताया। राठौड़ ने कहा कि एसआरआर कार्य न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि मताधिकार के दुरुपयोग को भी रोकने में सहायक सिद्ध होगा।

राठौड़ ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें मृत व्यक्तियों के नाम हटाने और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शामिल है। राजस्थान में भी इस प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है, ताकि केवल वैध और योग्य नागरिक ही मताधिकार का उपयोग कर सकें।
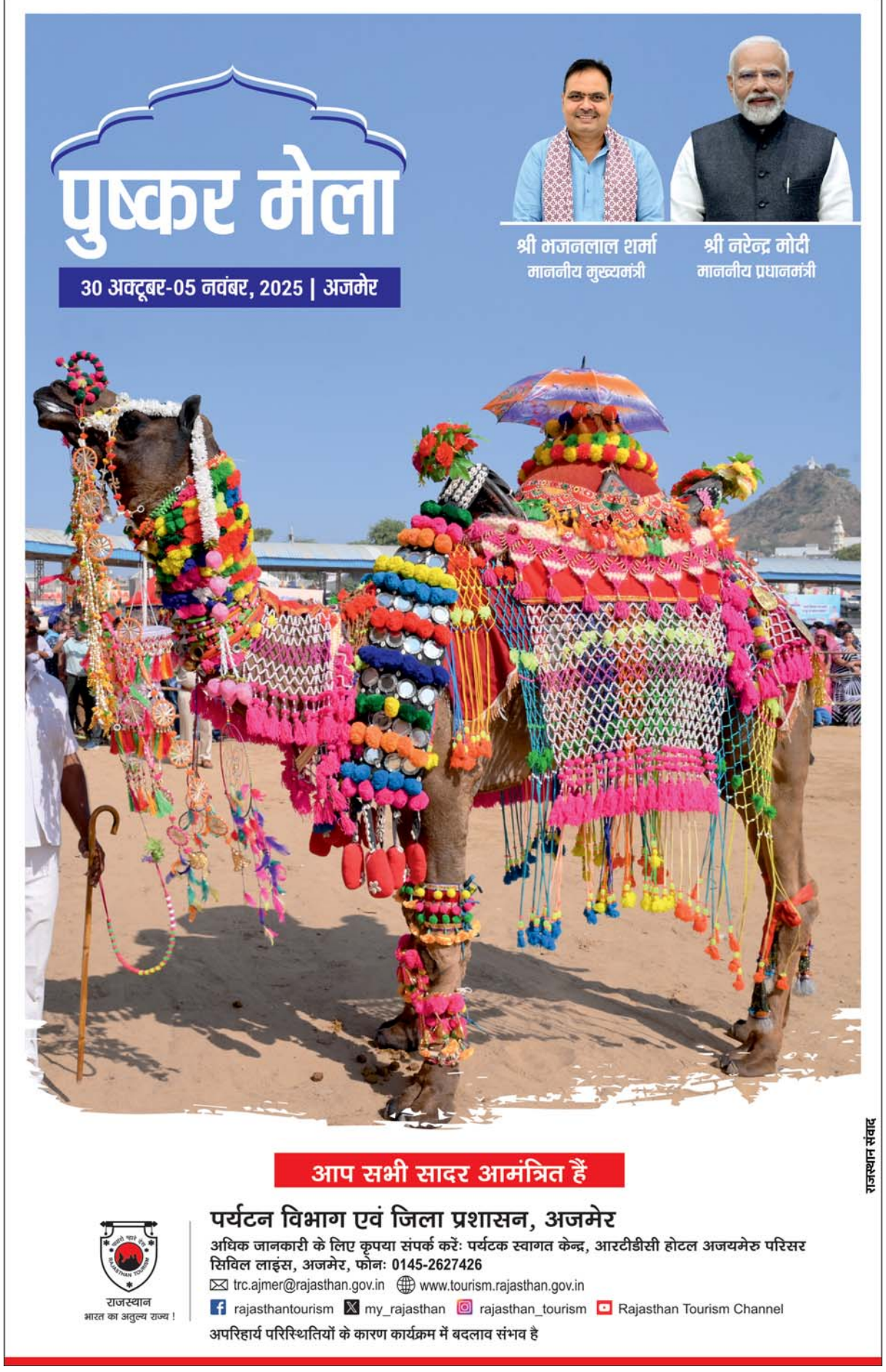
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि दुर्भाग्यवश, बीते वर्षों में कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थवश ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वा दिए हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। कुछ क्षेत्रों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम भी मतदाता सूची में शामिल होने की शिकायतें मिली हैं। ऐसे लोग भारत को एक धर्मशाला की तरह समझकर यहां केवल लाभ उठाने आते हैं, परंतु राष्ट्रिहत या जनसेवा से उनका कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे अवैध रूप से जुड़े नामों को मतदाता सूची से हटाना पूरी तरह उचित और आवश्यक कदम है। उन्होंने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि जो दल इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, वे वास्तव में अपने कथित वोट बैंक की राजनीति बचाने में लगे हैं, न कि लोकतंत्र की रक्षा में। राठौड़ ने स्पष्ट किया कि इस देश पर शासन करने का अधिकार उसी को है जो भारत माता के प्रति आत्मीयता रखता है, देशहित और जनहित की सच्ची चिंता करता है।